



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938

No. 775]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

का. आ. 865(अ).—जबकि सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है तथा आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है;

तथा जबकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)' (जिसे इसके पश्चात् योजना कहा जाएगा) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का संचालन कर रहा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (जिसे इसके पश्चात् एनएसकेएफडीसी कहा जाएगा) को अनुदान प्रदान किया जाता है।

तथा जबकि, एनएसकेएफडीसी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजर्स तथा उनके आश्रितों (जिन्हें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा जाएगा) को आगे एकबारगी नकद सहायता, पूंजीगत सब्सिडी तथा कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता (जिसे इसके पश्चात् लाभ कहा जाएगा) प्रदान करता है।

तथा जबकि, एनएसकेएफडीसी तथा इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित उपर्युक्त योजना के लिए किया जाने वाला व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामतः:-

1. (1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं;
- (2) योजना के तहत लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है अथवा जिनका अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं हुआ है, परन्तु वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, **30 जून, 2017** तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करेगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो, और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) में जा सकते हैं।
- (3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एनएसकेएफडीसी तथा इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां जिन्हें व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, के माध्यम से यह अपेक्षित है कि उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करें जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा निवास स्थान के समीप यथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रखंड, तालुक या तहसील में किसी आधार नामांकन केन्द्र के नहीं होने की स्थिति में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एनएसकेएफडीसी तथा इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

बशर्ते कि उस समय तक जब लाभार्थियों को आधार सौंपा जाता है, तब तक निम्नलिखित पहचान संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्येधीन ऐसे लाभार्थियों को योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा, नामतः:-

- (क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या
- (ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या
- (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; अथवा
- (iii) राशन कार्ड, अथवा
- (iv) राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय लेटर हैड पर जारी ऐसे सदस्य का फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र, अथवा
- (v) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के तहत लाभार्थियों को सुविधाजनक एवं बिना किसी कठिनाई के लाभ प्रदान करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एनएसकेएफडीसी तथा इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित सहित अपेक्षित सभी व्यवस्था करेगा :-

- (क) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को अवगत करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध समीपवर्ती आधार नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) उपलब्ध करायी जाएगी।
- (ख) यदि, लाभार्थी अपने निवास के समीप यथा प्रखंड, तालुक अथवा तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एनएसकेएफडीसी तथा इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे, कार्यान्वयन एजेंसी के संबंधित कार्मिक को अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं।
3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14016/04/2017-डीबीटी]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2017

S.O. 865(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is administering a Central sector scheme namely, Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) (hereinafter referred to as the Scheme) under which grants are provided to National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (hereinafter referred to as NSKFDC);

And whereas, NSKFDC in turn through its implementing agencies provides financial assistance to the identified manual scavengers and their dependents (hereinafter referred to as the beneficiaries) in the form of one time cash assistance, capital subsidy and skill training (hereinafter referred to as the benefits);

And whereas, the aforesaid Scheme implemented through NSKFDC and its implementing agencies, involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the scheme shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provision of section 3 of the said Act, and-such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Social Justice and Empowerment through NSKFDC and its implementing agencies which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block, Taluka or Tehsil, the Ministry of Social Justice and Empowerment through NSKFDC and its implementing agencies may facilitate in providing Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:—

- (a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and
- (b) (i) Bank passbook with photograph; or
- (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or
- (iii) Ration Card, or
- (iv) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or
- (v) any other documents specified by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the purpose;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Social Justice and Empowerment for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry of Social Justice and Empowerment through NSKFDC and its implementing agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

- (a) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.
- (b) in case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in Block, Taluka or Tehsil, the Ministry of Social Justice and Empowerment through NSKFDC and its implementing agencies are required to facilitate Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the implementing agencies or through a web portal provided for that purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 14016/04/2017-DBT]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.